सांध्य दैनिक

4PM

जिद...सच की

www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork @Editor_Sanjay YouTube @4pm NEWS NETWORK

● वर्षः 9 ● अंकः 143 ● पृष्ठः 8 ● लखनऊ, शुक्रवार, 30 जून, 2023

मूल्य ₹ 3/-

कठिनाईयों से भरी इस दुनिया में जिसे अपने आप पर भरोसा होता है वही विजेता कहलाता है।
-गुरु नानक देव

राज्यपाल के फैसले के खिलाफ कोर्ट ... 8 | समान अचार सहिंता, सियासी... 3 | फोनपे पर गरमाई मप्र की... 7

जलते मणिपुर में सियासी घमासान राहुल ने लगाया पीड़ितों पर मरहम

गांधी के दौरे पर भड़की भाजपा, कांग्रेस ने कहा-डर गई है मोदी सरकार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

इंफाल। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वहां पहुंच कर लोगों का हाल जाना और शांति की अपील की। शिविरों का दौरा करने के बाद वह राज्यपाल से भी मिले। राहुल गांधी की यात्रा के बाद भाजपा आगबबूला हो गई। वह कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है तो विपक्ष कह रहा है कि भाजपा डर गई है इसलिए राहुल गांधी की यात्रा को रोकने का प्रयास कर रही है।

वहीं मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। राज्य के नौ विधायकों ने भी बीते दिनों प्रधानमंत्री कार्यालय में पीएम मोदी के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। विधायकों ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार जनता के बीच अपना भरोसा खो चुके हैं। एन बीरेन सिंह पर आदिवासी विरोधी एजेंडे को बढ़ाने के आरोप लग रहे हैं। बीते दिनों जब केंद्र सरकार ने मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए शांति समिति गठित की थी तो उसमें भी शामिल किए गए कई लोगों ने एन बीरेन सिंह के नेतृत्व के खिलाफ असंतोष जाहिर किया था और मुख्यमंत्री को शांति समिति में शामिल करने का विरोध किया था।

राहुल गांधी ने की राज्यपाल से मुलाकात, सीएम बीरेन सिंह की मुश्किलें बढ़ीं

शांति बनाए रखें लोग : राहुल

इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर में राहत शिविरों का दौरा किया और इसके बाद राज्यपाल से भी मुलाकात की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि मणिपुर को शांति की जरूरत है। मैं राहत शिविर में गया और हर समुदाय के लोगों से मिला। राहत शिविरों में दवाई, खाने की कमी है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मेरी मणिपुर के हर व्यक्ति से अपील है कि शांति बनाए रखें। मैं यहां मौजूद हूं और जो शांति कि लिए कर सकता हूं वह करूंगा।

राज्यपाल से मिलेंगे सीएम बीरेन

मणिपुर में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के पद से इस्तीफा देने की अटकलें चल रही हैं। दरअसल सीएम एन बीरेन सिंह थोड़ी देर में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक, एन बीरेन सिंह सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। एन बीरेन सिंह शाम तीन बजे के करीब राज्यपाल अनुसुइया उइके से राजभवन में मुलाकात करेंगे।

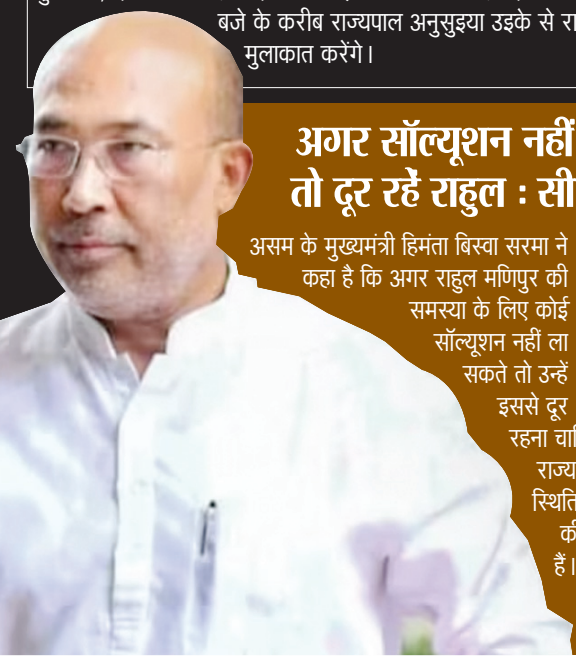

अगर सॉल्यूशन नहीं ला सकते तो दूर रहें राहुल : सीएम हिमंता

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा है कि अगर राहुल मणिपुर की समस्या के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं ला सकते तो उन्हें इससे दूर रहना चाहिए। उन्होंने कहा- राज्य और केंद्र सरकार स्थिति को काबू में करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में किसी नेता को वहां नहीं जाना चाहिए।

योगी ने लाभार्थियों को सौंपी चाबी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

» अतीक की छुड़ाई भूमि पर बने आवासों का लोकार्पण

प्रयागराज। मुख्यमंत्री योगी ने प्रयागराज जिले के लूकरगंज में अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई भूमि पर बने पीएम आवास का लोकार्पण किया।

शुक्रवार को निर्धारित समय से कुछ विलंब से पहुंचे सीएम ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर आवास का लोकार्पण किया। इसके बाद कार्यक्रम स्थल लीडर रोड पर औपचारिक रूप से लाभार्थियों को चाबी सौंपी। सुबह से ही बारिश होने के कारण कार्यक्रम में काफी अव्यवस्था रही। सीएम के आगमन के मद्देनजर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। लूकरगंज आवास से लेकर लीडर रोड तक पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है।

हाईकोर्ट ने दिया ट्विटर को झटका

» केंद्र के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज

» 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

बेंगलुरु। कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ लगाई गई ट्विटर की याचिका खारिज कर दी है। ट्विटर ने कुछ लोगों के अकाउंट, ट्वीट और यूआरएल ब्लॉक करने के केंद्र सरकार के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी थी।

कोर्ट ने केंद्र के आदेश न मानने के चलते ट्विटर पर 50 लाख रुपए का फाइन भी लगाया। केंद्र सरकार ने फरवरी 2021 से 2022 के बीच ट्विटर को किसान आंदोलन और कोरोना वायरस से जुड़े कुछ अकाउंट्स, ट्वीट और यूआरएल ब्लॉक करने का आदेश दिया था। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने पिछले साल जून में ट्विटर को नोटिस भेजा था कि केंद्र सरकार के आदेश न मानने पर कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ट्विटर ने इसके खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। 26 जुलाई, 2022 को जस्टिस कृष्णा सिन्हा की सिंगल जज बेंच ने इस पर पहली बार सुनवाई की। इसके बाद केंद्र सरकार और ट्विटर दोनों ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा।

हाईकोर्ट ने इस साल 21 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 30 जून को फैसला सुनाया और 45 दिन के अंदर जुर्माना जमा करने के लिए कहा। फरवरी 2021 में किसान आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार के आदेश पर ट्विटर ने किसान एकता मोर्चा समेत कई अकाउंट ब्लॉक भी किए थे।

अकाउंट ब्लॉक करने की वजह बतानी थी : ट्विटर

ट्विटर ने कोर्ट में कहा कि केंद्र सरकार के पास सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए सामान्य आदेश जारी करने का अधिकार नहीं था। सरकार को इसके लिए अकाउंट ब्लॉक करने की वजह बतानी थी, जिससे कंपनी यूजर को बता सके कि उसका अकाउंट किस वजह से ब्लॉक किया गया है। वहीं, सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए ट्विटर को ब्लॉक करने के आदेश दिए गए थे, जिससे लिंचिंग और मॉब वॉयलेंस की घटनाओं को रोका जा सके।

भाजपा की गलत नीतियों से बढ़ी महंगाई : अखिलेश

बोले- सरकार हर मोर्चे पर फेल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर फिर हमला बोला। उन्होंने कहा है जबसे मोदी व योगी सरकार आई है आम आदमी को सुख-चैन गायब हो गया है। उन्होंने कहा कि कहा कि जब से भाजपा सत्ता में आई है महंगाई आसमान छू रही है। पूंजीपरस्त और गलत नीतियों के कारण महंगाई नियंत्रण से बाहर चली गयी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। झूठे वादे कर सरकार में आई भाजपा न महंगाई रोक पाई और न ही बेरोजगारी कम कर पाई है।

गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने लखनऊ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। इसे एक शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। हालांकि, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर देश में बन रहे माहौल को भी इससे जोड़ा जा रहा है। सपा के ट्विटर अकाउंट से मुलाकात की एक तस्वीर पोस्ट की गई है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला की लखनऊ में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी शिष्टाचार भेंट। कयास लगाए जा रहे हैं कि विपक्षी एकता की बैठक में पटना में शामिल रहे अखिलेश यादव 2024 में कांग्रेस से हाथ मिला सकते हैं। हालांकि, अखिलेश पहले कह चुके हैं कि जिन राज्यों में जो भी पार्टी ज्यादा प्रभावी है कांग्रेस उसका समर्थन करे। शंकर सिंह वाघेला लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी के बारे में दिए गए उनके कई बयान चर्चा में रहे हैं।

शंकर सिंह वाघेला से मिले सपा प्रमुख

चंद्रशेखर पर हमला, यूपी में कानून व्यवस्था बेहाल : शिवपाल

सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अराजक तत्व अपनी सभी हदों और सरहदों को तोड़ने लगे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यूपी में विपक्षी नेता, अब सत्ता पक्ष और अपराधियों दोनों के निशाने पर हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर हुआ जानलेवा हमला प्रदेश के खोखले हो चुकी कानून-व्यवस्था के लिए घंटी है कि जाग जाओ सरकार।

सरकार को सिख, जैन और ईसाईयों का रुख भी जानना चाहिए : पवार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

मुंबई। देश में फिलहाल समान नागरिक संहिता एक बड़ा मुद्दा बन गया है। भाजपा, आप और जदयू सहित कुछ पार्टियां जहां इसका समर्थन कर रही हैं वहीं कुछ पार्टियां लगातार इसका विरोध भी कर रही हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कानून आयोग को यूसीसी पर 900 से अधिक मत प्राप्त हुए हैं। सरकार को सिख, जैन और ईसाई समुदाय का रुख भी जानना चाहिए।

कहा जा रहा है कि सिखों का इस कानून को लेकर अलग रुख है। बिना सिख समुदाय के संज्ञान के यूसीसी पर अपना रुख नहीं बता सकता कि मैं बिल का समर्थन कर रहा हूं या उसका विरोध। प्रधानमंत्री द्वारा अगर कुछ मुद्दों पर स्पष्टता दी जाए तो राकांपा अपना रुख तय करेगी। उन्होंने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि यूसीसी सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए हो, क्योंकि सत्ता से लोगों की नाराजगी है। शरद पवार ने पहली बार स्वीकार किया कि साल 2019 में महाराष्ट्र में भाजपा के साथ सरकार बनाने के लिए बातचीत हुई थी, लेकिन बाद में जब उन्होंने अपना स्टैंड बदल दिया तो फिर भाजपा ने तड़के चोरी-छिपे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। पवार ने कहा, भाजपा सत्ता के बिना नहीं रह सकती और सत्ता के लिए किसी के साथ जा सकती है।

आतिशी मार्लेना को वित्त एवं राजस्व मंत्रालय की भी मिली जिम्मेदारी

» केजरीवाल कैबिनेट में फेरबदल को उपराज्यपाल की मंजूरी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। आतिशी मार्लेना को दिल्ली सरकार में वित्त एवं राजस्व मंत्री नियुक्त कर दिया गया है। उपराज्यपाल से अनुमति मिल जाने के बाद अब वे दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरी सबसे पावरफुल मंत्री बन गई हैं। उनके पास वित्त मंत्रालय के अलावा ऊर्जा, पीडब्ल्यूडी, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास और पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण विभाग हैं। पहले यह भूमिका मनीष सिसोदिया की थी, जो अरविंद केजरीवाल के बाद पार्टी में नंबर दो की तरह से देखे जाते थे।

अहम प्रश्न है कि अरविंद केजरीवाल ने कैलाश गहलोत के स्थान पर आतिशी पर इतना भरोसा क्यों जताया?

सिसोदिया ब्लैकमेल कर रहे : सचदेवा

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ब्लैकमेल कर रहे हैं। सिसोदिया के दबाव का नतीजा है कि मुख्यमंत्री ने यह झूठ फैलाने की कोशिश की कि उपराज्यपाल पोर्टफोलियो फेरबदल की फाइल को रोक रहे हैं, जबकि उपराज्यपाल ने एक दिन के भीतर ही फाइल को मंजूरी दे दी थी। सचदेवा ने कहा है कि हर कोई जानता है कि पीडब्ल्यूडी के साथ वित्त और राजस्व दिल्ली सरकार के सबसे महत्वपूर्ण विभाग हैं। सिसोदिया के जेल जाने के बाद केजरीवाल ने वित्त और राजस्व को एक अन्य वरिष्ठ मंत्री कैलाश गहलोत को आवंटित कर दिया था। वित्त एक ऐसा विभाग है जिसके माध्यम से आम आदमी पार्टी धन संग्रह करती थी।

यूसीसी लागू करने से कहीं तूफान न आ जाए

» अब्दुल्ला बोले-परिणामों पर पुनर्विचार करे सरकार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

जम्मू। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष एवं सांसद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर जोर नहीं देना चाहिए और इसे लागू करने के परिणामों पर पुनर्विचार करना चाहिए। उन्हें इस सब पर विचार करना चाहिए और इसे आगे बढ़ाने के बजाय इसके परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि तूफान आ जाए। उनकी टिप्पणी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यूसीसी के लिए कड़ी वकालत करने के दो दिन बाद आई है।

फारूक अब्दुल्ला ने हजरतबल में ईद-उल-अजहा की नमाज अदा करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत के दौरान ये कहा। उन्होंने कहा, उन्हें (केंद्र सरकार) इस बारे में दोबारा सोचना चाहिए। यह एक विविधतापूर्ण देश है, यहां विभिन्न नस्लों और धर्मों के लोग रहते हैं और मुसलमानों का अपना शरिया कानून है। फारूक अब्दुल्ला ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू-कश्मीर आने वाले तीर्थयात्रियों का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा, मैं यात्रा का स्वागत करता हूं। मैं अल्लाह से प्रार्थना करता हूं कि यह सफल हो और यात्री आशीर्वाद लेकर लौटें।

कुछ लोगों ने देशभक्ति का ठेका ले रखा है : रफीक

राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग चेयरमैन और विधायक रफीक खान ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जयपुर में मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी लोगों को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। इसलिए सभी को विचार व्यक्त कर अपनी बात कह सकते हैं। संविधान में कोई भी संशोधन होता है तो उसे लेकर बातचीत की जाती है। आज बहुत सारे लोग देश भक्ति के नाम पर ठेकेदार बनकर बैठ गए हैं। जिन लोगों ने आजादी में कुछ नहीं किया था वे लोग आज देश को बेचने का काम कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान के नाम पर झगड़े करवा रहे हैं। देशभक्ति की खूब सारी बातें हो रही हैं।

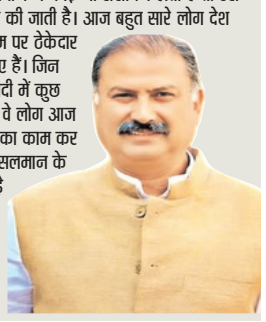

राजभवन में एक साथ पहुंचे नीतीश-मोदी

» मंत्रिमंडल का एक और विस्तार, सीएम ने विकास कार्य का लिया जायजा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

पटना। बिहार के राजभवन से जब यह खबर आई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा कोटे से उनके साथ लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे सुशील कुमार मोदी एक साथ अंदर हैं तो राजनीतिक तापमान अचानक चढ़ गया। दोनों अलग-अलग काम से, अलग समय पर गए थे, लेकिन दोनों के एक समय में अंदर होने से अफवाहों का बाजार गरम हो गया। मुख्यमंत्री को 10 जुलाई से पहले मंत्रिमंडल विस्तार करते हुए राजभवन में ही शपथ ग्रहण समारोह कराना है।

राजभवन के अंदर चल रहे निर्माण कार्यों को मुख्यमंत्री ने देखा और इसपर संबंधित अफसरों से बात भी की। अगले महीने के पहले पखवारे में ही बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू होना है और लगभग उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ शिमला में विपक्षी एकता को लेकर दूसरी बैठक की तैयारी हो रही है। इस बैठक में कांग्रेस की अहम भूमिका होगी, इसलिए कांग्रेस की दो और मंत्रीपद की मांग इससे पहले पूरी होनी तय है। संकट फिलहाल यह फंस रहा है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बाहर गए हुए हैं।

कांग्रेस ने मांगा मंत्री पद, मगर तेजस्वी मौन

जिनकी वजह से मिली कुर्सी उनका लिहाज करो नीतीश बाबू : अमित शाह

सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अभी-अभी पलटू बाबू पूछ रहे थे कि नौ साल में क्या किया? अरे नीतीश बाबू, जिनके साथ इतना बैठे हो, जिनके कारण मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हो- उनका तो लिहाज करो। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 20 साल से राहुल बाबा को लांचिंग किया जा रहा है। इस बार भी कांग्रेस ने पटना से राहुल गांधी को लॉन्च किया। बिहार की जनता भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं जाती है। 2024 में जनता को तय करना है कि 20 बार फेल लॉन्चिंग करने वाले राहुल बाबा चाहिए या नरेंद्र मोदी चाहिए। 2024 में मोदीजी देश का नेतृत्व करना चाहते हैं। अमित शाह ने पूछा कि जंगलराज वालों से बिहार को मुक्त कराओगे क्या? जो लोग सत्ता के लिए लालू-नीतीश के साथ जा रहे हैं, वह बिहार की चरमराती व्यवस्था देख लें। खराब मौसम में आने के लिए लोगों का धन्यवाद दिया। अमित शाह ने कहा कि जिन्होंने विश्वासघात किया है, उन्हें दंड देने का काम मुंगेर लोकसभा वालों को करना है। जनता से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि 2024 में मोदीजी को जिताओगे, 2025 में भाजपा को जिताओगे। सभी सीटें भाजपा को दिलाने की बात सोचकर मुट्ठी भींचिए और जोर से बोलिए भारत माता की।

समान अचार सहिंता, सियासी या समाजी शिगूफा

मुस्लिम पक्षकार बोले-पर्सनल लॉ पर हस्तक्षेप अनुचित

» भाजपा कर रही ध्रुवीकरण : कांग्रेस

» टीएमसी बोली चुनावी हथकंडा

» संविधान के आर्टिकल 44 में है इसका जिक्र

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। भोपाल में समान आचार सहिंता (यूसीसी)पर प्रधानमंत्री के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों से भी प्रतिक्रिया आने लगी है। कांग्रेस ने इसे मुद्दों से भटकाने वाला बताया है तो टीएमसी ने चुनावी शिगूफा कह कर किनारा कर लिया है। जबकि आम आदमी पार्टी ने सैद्धांतिक सहमति की बात कर सत्ता पक्ष को राहत देने वाला काम किया। वहीं मुस्लिमों की आवाज उठाने वाले नेता इसे मोदी सरकार का दिखावा बता रहे है तो कुछ कह रहे हैं ये मुस्लिमों के धार्मिक अधिकारों का हनन करने वाला बनेगा और आपसी सौहाद्र खराब होगा।

विपक्षी दलों ने इसे लोकसभा चुनाव 2024 से पहले वोटों के ध्रुंवीकरण की कोशिश के तौर पर पेश किया है, वहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी तक ने यूसीसी पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। मुस्लिम समुदाय यूसीसी को धार्मिक मामलों में दखल के तौर पर देखते हैं। यूसीसी का विरोध करने वाले मुस्लिम धर्मगुरुओं का मानना है कि यूसीसी की वजह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि शरीयत में महिलाओं को संरक्षण मिला हुआ है। वहीं, यूसीसी के जरिए मुसलमानों पर हिंदू रीति-रिवाज थोपने की कोशिश किए जाने का शक है।

मोदी सरकार के तरीके से सहमत नहीं : आप

आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वह सैद्धांतिक रूप से समान नागरिक संहिता के पक्ष में है लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार इसे लागू करना चाहती उसके खिलाफ है। आम आदमी पार्टी से राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कहा है कि सैद्धांतिक तरीके से हम इसका (यूसीसी) समर्थन करते हैं, मगर केंद्र सरकार जिस तरह से इसे लागू करना चाहती है, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। संदीप पाठक ने कहा कि आर्टिकल 44 भी इसका समर्थन करती है कि देश में यूसीसी होना चाहिए। चूंकि यह मुद्दा ऐसा है जो देश के सभी धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ इसके लिए बड़े स्तर पर विचार विमर्श होना चाहिए। देश के सभी वर्गों का सुझाव, सभी पार्टियों से विचार-विमर्श होना चाहिए। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन्हें रिवर्स नहीं किया जा सकता है, ऐसे में उस पर प्रॉपर बहस और विचार होना चाहिए, यह मुद्दा भी वैसा ही है।

संविधान देता है भारत के लोगों के बीच विविधता तथा बहुलता को मान्यता

आभासी तौर पर उनकी तुलना सही प्रतीत हो सकती है, लेकिन सच्चाई काफी अलग है। एक परिवार का तानाबाना रक्त संबंधों से बनता है, एक राष्ट्र को एक संविधान से जोड़ा जाता है, जो एक राजनीतिक-कानूनी दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि एक परिवार में भी विविधताएं होती हैं, भारत का संविधान भारत के लोगों के बीच विविधता तथा बहुलता को मान्यता देता है। गौरतलब है कि समान नागरिक संहिता लंबे समय से भाजपा के तीन प्रमुख चुनावी मुद्दों में से एक रही है, जिसमें दूसरा जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करना और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण है। विधि आयोग ने 14 जून को यूसीसी पर नए सिरे से विचार-विमर्श की प्रक्रिया शुरू की थी और राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस मुद्दे पर सार्वजनिक और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों सहित हितधारकों से राय मांगी थी।

यूसीसी मतलब एक ही तरह का कानून

समान नागरिक संहिता दरअसल एक देश एक कानून की विचारधार पर आधारित है। ष्टष्ट के अंतर्गत देश के सभी धर्मों और समुदायों के लिए एक ही कानून लागू किया जाना है। समान नागरिक संहिता का अर्थ यूनिफॉर्म सिविल कोड में संपत्ति के अधिग्रहण और संचालन, विवाह, तलाक और गोद लेना आदि को लेकर सभी के लिए एकसमान कानून बनाया जाना है।

कांग्रेस को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए : नकवी

इधर, बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि समान नागरिकता संहिता पर कांग्रेस को अपना रुख स्पष्ट करना पड़ेगा। क्या वो यूसीसी के समावेशी कानून के साथ है या सांप्रदायिक करतूत के साथ है।

रिफॉर्म बेहद जरूरी, राजनीति करना ठीक नहीं : जमीयत सदस्य

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय सचिव नियाज अहमद फारुकी ने कहा कि रिफॉर्म बेहद जरूरी हैं, लेकिन उस पर राजनीति करनी ठीक नहीं है। यही वक्त है, कॉमन सिविल कोड को लाने का। दुनिया के 80 देशों में ये कानून है, क्या वहां धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है? आजादी के बाद भी ज्यादातर लोग इसके पक्ष में थे। फिर ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, इसके दायरे में हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग आएंगे। हालांकि, पीएम मोदी के बयान के बारे में पूछने पर अहमद फारुकी ने कहा कि ये प्रधानमंत्री ने राजनीतिक बयान दिया है। प्रधानमंत्री को ये बयान नहीं देना चाहिए था। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बयान देकर 2024 चुनाव की पिच तैयार की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में हम अपना ड्राफ़्ट तैयार कर लॉ कमीशन से मिलेंगे।

यूसीसी कोई नया मुद्दा नहीं : अवस्थी

समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने बताया कि विधि आयोग द्वारा नोटिस के संचार के बाद हमें समान नागरिक संहिता पर भारी प्रतिक्रिया मिली है। कल तक हमें 8.5 लाख प्रतिक्रियाएं मिल चुकी हैं। उन्होंने कहा कि यूसीसी कोई नया मुद्दा नहीं है, संदर्भ 2016 में प्राप्त हुआ था, एक परामर्श पत्र 2018 में जारी किया गया था। 2018, नवंबर 22 तक, विधि आयोग कार्यात्मक नहीं था। 22 नवंबर को नियुक्ति यां की गईं और इस मामले को उठाया गया और हम उस पर काम कर रहे हैं। समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी कहते हैं कि हम सभी हितधारकों और संगठनों के साथ व्यापक परामर्श करने का प्रयास कर रहे हैं।

मुस्लिमों के अधिकारों के हनन की कोशिश : मुस्लिम धर्मगुरु

यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) यानी देश के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के नियम एक होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार (27 जून) को एक कार्यक्रम के दौरान यूसीसी का जिक्र करते हुए कहा कि एक घर में दो कानून कैसे चल सकते हैं? उन्होंने कहा कि इस मुद्दे से मुस्लिमों को गुमराह किया जा रहा है। इससे पहले लॉ कमीशन ने यूसीसी को लेकर सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों से 30 दिनों के भीतर उनके विचार मांगे थे। एआईएमआईएम चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, केंद्र सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ इसलिए लाना चाहते हैं कि मुस्लिम अक्लियत को उनके मजहब से उनकी मजहबी शिनाख्त को कमजोर करके रख दिया जाए। अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो नहीं कर सकता. जब तक इजाजत न ले। ओवैसी ने कहा, इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रेक्ट है हिंदू में जन्म-जन्म का साथ, यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं, हिंदू सिविल कोड की बात है.। भारत के मुसलमान को टारगेट करना मकसद है. एक तरफ आप पसमांदा मुसलमानों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। दूसरी तरफ आपके प्यादे उनकी मस्जिदों पर हमला कर रहे हैं, उनकी लिंचिंग के जरिए हत्या कर रहे हैं।

फिरकापरस्त लोगों की तरफ से ये एक सियासी मसला : अरशद मदनी

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने यूसीसी को लेकर कहा, 1300 साल से पूरी दुनिया और भारत का मुसलमान जिस पर्सनल लॉ के तहत अपनी जिंदगी गुजार रहा है, हम उसे ही जरूरी समझते हैं और उसे रखना चाहिए, हम यूसीसी के खिलाफ कोई एहतजाज या सड़कों पर नहीं उतरेंगे, ये फिरकापरस्त लोगों की तरफ से ये एक सियासी मसला है। इसकी कोई वास्तविकता नहीं है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा, इस्लाम की मजहबी पॉलिसी अलग है, हिंदू-सिख-ईसाईयों की अलग है, सबकी पॉलिसी अलग-अलग है तो उन्हें एक जैसा कैसे किया जा सकता है।

मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश : चिदंबरम

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की पुरजोर वकालत किए जाने के एक दिन बाद कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा कि 'एजेंडा आधारित बहुसंख्यक सरकार इसे लोगों पर थोप नहीं सकती, क्योंकि इससे लोगों के बीच 'विभाजन बढ़ेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि प्रधानमंत्री बेरोजगारी, महंगाई और घृणा अपराध जैसे मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए समान नागरिक संहिता की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समान नागरिक संहिता का इस्तेमाल समाज के ध्रुवीकरण के लिए कर रही है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सुशासन में नाकाम रही भाजपा अगला चुनाव जीतने के लिए मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने के लिए यूसीसी का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने यूसीसी की वकालत करते हुए एक देश की तुलना एक परिवार के साथ की है।

जिद... सच की

Sanjay Sharma
editor.sanjaysharma
@Editor_Sanjay

लोकतंत्र के लिए चुनाव में हिस्सा लेना जरूरी

"ध्यान रहे, 2018 में पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों का जम्मू-कश्मीर के दोनों प्रमुख दलों- नैशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी- ने बहिष्कार किया था। चूंकि वे चुनाव पीडीपी-बीजेपी सरकार गिरने और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के बाद हो रहे थे, इसलिए दोनों दलों ने यह कहते हुए इसका विरोध किया था कि राज्य में कोई निर्वाचित सरकार नहीं है।

जम्मू-कश्मीर में आर्टीकल-370 हटे हुए पांच साल से ऊपर हो गए हैं। ह वहां की सियासी पार्टियों से लेकर आमजन तक चाहते हैं कि अब वहां पर चुनाव होने चाहिए। राज्य की प्रमुख पार्टी नेशनल कांफ्रेंस व पीडीपी ने कहा कि वह राज्य की सभी चुनावों में हिस्सा लेगी। यह फैसला जम्मू-कश्मीर के लोकतंत्र केलिए लाभकारी होगा। चुनाव से आमजन की चुनी हुई सरकार आएगी तो वह उनकी समस्याओं पर ध्यान देंगे। गौरतलब हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का यह बयान महत्वपूर्ण है कि उनकी पार्टी अब जम्मू-कश्मीर में होने वाले हर चुनाव में शामिल होगी। उन्होंने कहा कि 2018 के बाद से पार्टी की सोच में काफी बदलाव आया है। ध्यान रहे, 2018 में पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों का जम्मू-कश्मीर के दोनों प्रमुख दलों- नैशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी- ने बहिष्कार किया था। चूंकि वे चुनाव पीडीपी-बीजेपी सरकार गिरने और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के बाद हो रहे थे, इसलिए दोनों दलों ने यह कहते हुए इसका विरोध किया था कि राज्य में कोई निर्वाचित सरकार नहीं है। उनका कहना था कि वे अपनी ऊर्जा विधानसभा चुनावों के लिए बचाकर रखना चाहते हैं। बहरहाल, उसके बाद 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को हासिल विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया और यह एक अलग राज्य भी नहीं रहा, दो केंद्र शासित क्षेत्रों में बंट गया। इसका विरोध करते हुए पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और नैशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला दोनों ने फिर चुनावों से दूर रहने का ही एलान किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर को मिला विशेष दर्जा वापस नहीं मिलता, वह चुनाव नहीं लड़ेंगी। इसी तरह उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिलने तक वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। निजी तौर पर चुनाव न लड़ने की दोनों नेताओं की घोषणा तो अभी कायम है, उसमें किसी तरह के संशोधन की बात इन लोगों ने नहीं कही है, लेकिन राज्य में चुनावों की जरूरत किसी न किसी रूप में सभी स्वीकारते हैं। जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक हलकों में इस मजबूत होते अहसास का संकेत है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली जरूरी है और किसी भी तर्क से इसमें बाधा डालना हर किसी के लिए नुकसानदेह होगा। यह अहसास इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अब जम्मू-कश्मीर में जल्द चुनाव की न सिर्फ जरूरत महसूस की जा रही है, बल्कि संभावना भी जताई जा रही है। इस बीच, केंद्र सरकार ने भी यहां शांति और विकास सुनिश्चित करने के प्रयास किए हैं।

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

सरकारी जवाबदेही व समाज की संवेदनशीलता जरूरी

क्षमा शर्मा

कोई भी दिवस किसी समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए घोषित किया जाता है। पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस मनाया जाना बताता है कि दुनिया में बुजुर्गों की स्थिति विकट है। हेल्पेज इंडिया का 60 से 90 वर्ष तक की आयु की शहरी-ग्रामीण करीब आठ हजार महिलाओं पर अध्ययन गहरे निहितार्थ?सामने लाता है।? अध्ययन में शामिल बीस राज्यों, पांच महानगरों और दो केंद्रशासित प्रदेशों की महिलाओं में से सोलह प्रतिशत ने बताया था कि उन्हें मारपीट सबसे अधिक झेलनी पड़ती है। साथ ही तमाम तरह की बदसलूकी जैसे कि बात-बात पर अपमान, गाली-गलौज , खाना न देना, मनोवैज्ञानिक मसले आदि शामिल हैं।

चौंकाने वाली बात यह कि सर्वे में शामिल चालीस प्रतिशत महिलाओं ने बुरे व्यवहार के लिए बेटों को जिम्मेदार माना। इकत्तीस प्रतिशत ने रिश्तेदारों के द्वारा हिंसा झेली तो सत्ताइस प्रतिशत ने इसके लिए बहुओं को जिम्मेदार माना। ज्यादा चिंताजनक बात यह कि ये महिलाएं परिवार और आसपास के लोगों से इतना डरती भी हैं कि पुलिस को बुरे व्यवहार की सूचना नहीं देती हैं। विडंबना है कि यह सिर्फ महिलाओं की ही समस्या नहीं है, बड़ी संख्या में पुरुष भी पीड़ित हैं। इस तरह का प्रामाणिक अध्ययन जरूर किया जाना चाहिए। सरकारी बेरुखी के बीच देश में बुजुर्गों की संख्या दस करोड़ के आसपास बताई जाती है। वे वोटर्स भी हैं लेकिन किसी राजनीतिक दल की चिंता के केंद्र में नहीं दिखाई देते। उन्हें तो एक तरह से फ्यूज बल्ब मान लिया जाता है जो किसी के काम के नहीं हैं, न समाज के, न सरकार के, न दो पैसे कमाने लायक बल्कि अपने हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर। इसीलिए बुजुर्गों के प्रति बदसलूकी बढ़ती जाती है और हम आंखें मूंदें रहते हैं। मीडिया भी इनकी समस्याओं की अनदेखी करता है क्योंकि बुजुर्गों के झुर्रीभरे चेहरे चैनल्स की चमकदार और युवा दुनिया के किस काम के।

बहुत दिन पहले एक वीडियो देखा था कि एक बेहद कृशकाय बूढ़ी महिला को एक युवा स्त्री घसीटकर लाती है और सड़क किनारे उसे उठा-उठाकर पटकती है, बार-बार। पीटती जाती है। बूढ़ी महिला चीख-चिल्ला रही है। रो रही है। वह बचने की कोशिश भी कर रही है, मगर बच नहीं पाती। उसे बचाने का प्रयास कोई राहगीर नहीं करता। बुढ़िया चिल्लाती रहती है, लेकिन लगता

है कि सड़क से गुजरते लोग बहरे हो गए हैं। यह बहरापन, हमें किसी से क्या मतलब की भावना और दूसरे के दु:ख से निरपेक्षता को दर्शाता है, जो हिंसा करने वालों का हौसला बढ़ाता है। और जब तक हम खुद हिंसा का शिकार न हों, हमें चिंतित भी नहीं करता। जो स्त्री उस बूढ़ी महिला को पीट रही थी, वह निश्चित तौर पर उसके परिवार की सदस्य ही रही होगी। बाहर के हिंसक व्यवहार से तो शायद निपटा भी जा सके, लेकिन परिजनों के हिंसक व्यवहार का निवारण कैसे हो। बुजुर्गों के प्रति अपनों द्वारा हिंसा, भेदभाव, प्रापर्टी अपने नाम कराकर उन्हें बेदखल कर देने आदि की खबरें लगातार आती रहती हैं। लेकिन शायद ही कोई इन पर ध्यान देता है। बल्कि सरकारों में बड़े पद पर बैठे बहुत से लोग ही बुजुर्गों को देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ बताने लगते हैं। हां अदालतें जरूर अकसर बुजुर्गों के पक्ष में फैसले देती हैं, मगर अदालतों तक कितने बुजुर्ग पहुंच पाते हैं। कितनों के शरीर में इतना दम होता है और संसाधन भी कि वे अदालतों तक पहुंच सकें। शहरों में ऐसे बुजुर्ग भी बड़ी संख्या में मिलते हैं जो स्वस्थ हैं। आर्थिक संसाधनों की भी कोई कमी नहीं, लेकिन उनके पास समय काटने का कोई साधन नहीं। जिनके बच्चे साथ रहते हैं, चाहे घर बुजुर्गों का ही हो, वहां कोई सम्मान नहीं। यह भावना भी बराबर बनी रहती है जैसे कि बच्चे उनके साथ रहकर उन पर बड़ा भारी अहसान कर रहे हों। कई बार तो बच्चे बुजुर्गों का सारा पैसा हड़प लेते हैं और उन्हें असहाय छोड़ देते हैं। ऐसे में यदि उनके साथ मारपीट और हिंसा भी होने लगे और अस्वस्थ होने की अवस्था में इलाज और देखभाल की भी कोई व्यवस्था न हो तो ये लोग कहां जाएं?

इनकी योग्यता के अनुसार इन्हें काम देकर समाज में इनकी भूमिका बढ़ सकती है। साथ ही इनका आत्मविश्वास भी बढ़ सकता है। हां, जो इनके प्रति बुरा सलूक करे, उससे भी सरकार निपटने की व्यवस्था करे, पुलिस बदसलूकी का संज्ञान ले, वरना तो इनका जीवन ही दूभर हो जाएगा। कुछ साल पहले एक मित्र अपना मकान बेचकर बेटे के पास अमेरिका चले गए। अभी गए एक महीना भी शायद नहीं बीता था कि उनका फोन रात के बारह बजे आया। उनका कहना था कि जब उनके बहू-बेटे दफ्तर चले गए हैं, तब वे फोन कर रहे हैं।

एमएसपी को कानूनी गारंटी में किसान की खुशहाली

देविंदर शर्मा

आखिरकार, हरियाणा सरकार किसानों को सूरजमुखी की 'उपयुक्त' कीमत अदा करने पर सहमत हो गयी है। कुछ समय पूर्व किसान इस मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे, और सरकार इनकार करती रही थी। किसानों ने विरोध जताने के लिए चंडीगढ़-दिल्ली हाईवे को बाधित किया, यातायात खुलवाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। किसान नेताओं को हिरासत में भी लिया। आंदोलनकारी किसानों ने सूरजमुखी की फसल के उचित भाव की मांग को लेकर एकजुटता दर्शायी। जबकि हरियाणा सरकार ने दावा किया था कि वह भावांतर भरपाई स्कीम के तहत किसानों को क्षतिपूर्ति दे रही थी लेकिन किसान पूर्व घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही फसल की खरीद किये जाने पर अड़ि थे। बतौर एमएसपी 6400 रुपये प्रति क्विंटल के बजाय किसानों को अपनी फसल 4200 से 4800 रुपये प्रति क्विंटल के बीच बेचने को मजबूर किया जा रहा था।

यहां तक कि राज्य सरकार के वादे के मुताबिक प्रति क्विंटल एक हजार रुपये क्षतिपूर्ति मिलने के बाद भी किसानों को प्रति क्विंटल 600 रुपये या उससे कुछ ज्यादा घाटा था। इससे सूरजमुखी उत्पादकों में वाजिब गुस्सा था। सूरजमुखी की समर्थन मूल्य पर खरीद से शुरुआती इनकार, फिर 'उचित' मूल्य भुगतान का समझौता, और वह भी प्रदर्शनकारी किसानों के सड़कों पर उतर आने के बाद- यह किसानों के विरुद्ध सरकारों का पूर्वाग्रह को ही दर्शाता है। हालांकि इसकी जड़ें 1930 के दशक में उन दिनों तक जाती हैं जब उद्योगपतियों का एक बॉम्बे क्लब नामक समूह कभी यह यकीनी बनाने की दिशा में काम करता था कि खाद्य पदार्थों की कीमतें कम रखी जाएं ताकि वेतन कम रखे जा सकें। दरअसल बरसों से कृषि को दरिद्र बनाए रखकर खाद्य कीमतों को कम रखने की यही आर्थिक सोच हावी रही है। इसलिए आर्थिक सुधारों को व्यवहार्य बनाए रखने को या कहें कि कंपनियों को मुनाफा कमाने की इजाजत देने के लिए कृषि को दांव पर लगाया जा रहा है।

हरियाणा का घटनाक्रम समझ से परे है कि पहले तो किसानों की उपयुक्त रेट की न्यायोचित मांग को नकार दिया गया और फिर सड़कों पर हंगामे के बाद सही कीमत देने को राजी भी हो गये। यह शुरू में ही क्यों नहीं किया गया? एमएसपी किसानों का हक है। यदि सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया होता तो कोई वजह ही नहीं थी कि किसान राजमार्ग पर आकर विरोध प्रदर्शन करते। वास्तव में, मैंने आज तक कभी किसी कॉरपोरेट दिग्गज को अपने बेड लोन की माफी को लेकर नई दिल्ली के जंतरमंतर पर प्रदर्शन करते नहीं देखा? यह भी कि दस वर्षों के 12 लाख करोड़ रुपये के बीमार कॉर्पोरेट ऋण को बिना किसी विरोध बैंक के रजिस्टर से कैसे हटा दिया गया? इतना ही काफी नहीं, आरबीआई ने जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों के लिए 'समझौता निपटान' की इजाजत दी है, जिनके पास भुगतान सामर्थ्य है लेकिन वे नहीं करते ताकि एक वर्ष बाद नए सिरे से लोन ले सकें। जबकि कृषि कर्ज पर डिफ़ॉल्टर हो जाने पर किसानों को नियमित तौर पर सलाखों के पीछे भेजा जाता है, जाहिर है आरबीआई चहेते पूंजीपतियों के लिए 'कवच' का काम करता है। मुझे खुशी है, ऐसे में जब मुख्यधारा के अर्थशास्त्री इस विकृति को लेकर साफ तौर पर चुप हैं, बैंक संघ खुले तौर पर आरबीआई की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं।

यह भेदभाव आर्थिक विश्लेषण में भी स्पष्ट दिखता है। बीती 14 जुलाई को एक अंग्रेजी दैनिक में एक लेख 'एमएसपी में मामूली वृद्धि सरकार द्वारा एक सख्त कदम है' प्रकाशित हुआ जिसमें दो अर्थशास्त्रियों ने 2023-24 विपणन सीजन के लिए खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में 7 प्रतिशत की अतिरिक्त मामूली बढ़ोतरी से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में खाद्य टोकरी के लिए भारित औसत की गणना की है। लेकिन यह सही नहीं है क्योंकि विपणन सत्र अभी शुरू होना है, और यह देखते हुए कि साल में एमएसपी पर केवल 14 फीसदी फसलें खरीदी जाती हैं, कीमतों में वृद्धि को पूरी फसल से जोड़ना जल्दबाजी होगी। शेष 86 फीसदी फसलों का ज्यादातर कारोबार एमएसपी से कम कीमत पर होगा। चुनाव पूर्व वर्षों में एमएसपी मूल्य वृद्धि के जरिये देखी गई बड़ी बढ़ोतरी भी गलत थी।

दूसरी ओर, जो लोग किसानों को दोषी ठहराते हैं कि वे बिना सोचे-विचारे जल्दबाजी में राजमार्गों और रेल पटरियों को बाधित करके बैठ जाते हैं, उन्हें भी अपना पूर्वाग्रह त्याग देना चाहिए। ऐसी आलोचना अनुचित ही होगी, और इससे शहर में जन्मे-पले लोगों की ग्रामीण देहात के बारे में समझ का पता चलता है। देश भर में किसानों के विरोध प्रदर्शनों की मामला-दर-मामला जांच करें, और आप देखेंगे कि उनके साथ कैसे ज्यादती हुई। वे एक आर्थिक षड्यंत्र के शिकार हैं जिसका मकसद असल में उन्हें ज़मीन से बेदखल करना है। दरअसल, पैदावार के सही दाम प्राप्ति के लिए किसानों के पास लट्ठ का सहारा लेने के अलावा अन्य कोई विकल्प कम ही है। यहां बड़ा सवाल यह उठता है कि नीति निर्माताओं में किसानों को गारंटीशुदा कीमत प्रदान करने को लेकर अनिच्छा क्यों हैं? प्रमुख तौर पर यह इसलिए है कि कॉलेज पाठ्यक्रम में इकोनॉमिक 101 यानी अर्थशास्त्र की शुरुआती मूल अवधारणाओं ने हमें यह यकीन करने के लिए मानसिक तौर पर तैयार किया है कि बाजार के तहत ही सर्वोत्तम कीमत प्राप्त होती हैं। वास्तव में, निराशाजनक ही है जब कुछ जनमत बनाने वाले भी किसानों को सही कीमत का आश्वासन प्रदान करने की जरूरत को चुनौती देते हैं।

बरसात में बच्चों का रखें ख्याल
नहीं तो पड़ेंगे बार-बार बीमार

मच्छरों को दूर रखें

मच्छर के काटने से नवजात शिशु को गंभीर परेशानियां हो सकती हैं, जिससे उनके शरीर पर रेडनेस और सूजन भी हो सकती है। ऐसे में बच्चे के मच्छरदानी में रखें, जिससे वे अच्छी और भरपूर नींद सो सकें। वहीं शाम के वक्त उन्हें पूरी तरह से ढके हुए कपड़े पहनाएं। अगर आपके पास मच्छरों को भगाने के लिए कोई नेचुरल रेमेडी है, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

बच्चे को कब नहलाएं?

बड़ों की तरह बच्चों को रोजाना नहाने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वे अपना अधिकांश समय घर के अंदर ही बिताते हैं। ऐसे में मानसून सीजन में बच्चे को हफ्ते में दो से तीन बार नहलाना काफी होगा। खासकर उमस भरे मौसम में, गर्मी से राहत दिलाने के लिए यह काफी होगा। लेकिन अगर आप बच्चे को बाहर लेकर गए हैं, तो उसे गुनगुने पानी से नहलाएं। बचपन की अधिकांश यादें बारिश में खेलने और कागज की नाव चलाने से बनती है। इसलिए उनकी यादों को बनने से रोकना नहीं है बल्कि सही देखभाल के जरिए उन्हें बरसात के मौसम का अधिकतम लाभ उठाने देना है।

बीमारियों को नजरअंदाज न करें

बुखार, शारीरिक दर्द, छींक आना और अन्य लक्षण मानसून से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा इस मौसम में वायरल इंफेक्शन होने का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे कोई भी लक्षण नजर आने पर सीधे अपने डॉक्टर से संपर्क करें और बीमारी से लड़ने के लिए उचित सावधानी बरतें, भले ही यह शुरुआती दौर में ही क्यों न हों।

बारिश से बचाएं

कोशिश करें कि अपने बच्चे को बारिश में भीगने से बचाएं। इसके लिए छाते, रेनकोट और रेन बूट जैसी आजमाई हुई चीजें आपके काम आ सकती हैं। बच्चों को बाहर ले जाने से पहले ध्यान दें कि उनके पास सभी आवश्यक चीजें हैं। बरसात के मौसम के दौरान, तापमान में भी तेजी से गर्माहट और ठंडक का अनुभव होता है। वहीं नमी से बचने के लिए बच्चों को आरामदायक सूती कपड़े पहनाएं, लेकिन जब मौसम ठंडा हो जाए, तो उन्हें थोड़े मोटे कपड़े पहनाएं। ध्यान रखें कि बच्चे के कपड़े पूरी तरह सूखे हों क्योंकि बरसात के मौसम में कपड़े नमी सोख लेते हैं, जिससे फंगल इंफेक्शन हो सकता है।

बीमारी से कैसे बचाएं?

बारिश के मौसम में पानी से होने वाले संक्रमण का खतरा काफी बढ़ जाता है, ऐसे में बच्चों के बीमार पड़ने की संभावना भी अधिक रहती है। इसलिए पहली बार माता-पिता बने कपल को अपने बच्चे को मानसून में स्वस्थ्य रखने के लिए अधिक सावधानी बरतने की जरूरत होती है। इसके लिए आदतों में कुछ बदलाव और थोड़ी सावधानी आपका काम काफी आसान कर सकती है।

मानसून बहुत जल्द दस्तक देने जा रहा है, जो धीरे-धीरे गर्मी का प्रचंड रूप शांत करके लोगों को राहत दिलाएगा। वहीं, गर्मी से बेहाल लोग भी बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, यह मौसम दूसरों के लिए जितना सुकून लेकर आएगा, नए माता-पिता के लिए उतनी ही परेशानियां क्योंकि मानसून का महीना केवल बारिश ही नहीं बल्कि बीमारी के लिए भी मशहूर है। ऐसे में नए पेरेंट्स अपने बच्चे का ख्याल कैसे रखें यह सबसे बड़ा सवाल है।

डायपर गीला न रहे

बरसात के मौसम में बच्चे को एक मिनट के लिए भी गीला डायपर न पहनने दें। सर्द या बरसात के दिनों में बच्चे अन्य मौसमों की तुलना में अधिक पेशाब करते हैं, जिससे उनकी स्किन पर रैशेज हो सकते हैं। इसके अलावा इंफेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है और उन्हें ठंड भी लग सकती है। इसलिए, याद रखें कि जैसे ही आपको लगे कि आपके बच्चे की नैपी गीली या गंदी हो गई है, तो उसे तुरंत बदल दें।

हंसना मना है

दो महिलाएं एक फंक्शन में गईं। वहां पहली महिला जिस भी जगह बैठने लगती तो दुसरी महिला उसकी बैठने की जगह को अपने दुपट्टे से साफ कर देती। तकरीबन पांच-दस बार ऐसा हुआ। तब किसी ने दूसरी महिला से पूछा कि तू खुद की बजाय, इस औरत की जगह क्यों साफ कर रही है? तो वो महिला बोली, क्या करूं बहना? ये मेरी जेठानी है ! और ये आज मेरी साड़ी पहन कर.. आई है।

गांव में आधार कार्ड बन रहा था। कम्प्यूटर ऑपरेटर ने एक महिला से पूछा- तुम्हारे घरवाले का क्या नाम है? ये कॉलम भरना है। महिला बोली— हमारे यहां घरवाले का नाम नहीं लिया जाता। ऑपरेटर- कुछ हिंट दो मैं भर देता हूं। महिला बोली — 3 गंजी 3 गंजी। ऑपरेटर चकरा गया। तभी बगल में खड़ा एक लड़का बोला— छगनजी?

एक लड़का क्लास में लड़की को रोज चुपके चुपके देखा करता था, एक दिन लड़का बोला- I Love You, लड़की- अगर मैं भी I Love You बोलूं, तो तुमको कैसा लगेगा? लड़का- जानम, मैं तो खुशी से मर जाऊंगा, लड़की बड़ी चालाक निकली, तिरछी नजर घुमा के बोली- जा नहीं बोलती, जी ले अपनी जिंदगी?

कहानी | चार विद्वान ब्राह्मण

बहुत पुरानी बात है। चार विद्वान ब्राह्मण मित्र थे। एक दिन चारों ने संपूर्ण देश का भ्रमण कर हर प्रकार का ज्ञान अर्जित करने का निश्चय किया। चारों ब्राह्मणों ने चार दिशाएं पकड़ीं और अलग-अलग स्थानों पर रहकर अनेक प्रकार की विद्याएं सीखीं। पांच वर्ष बाद चारों अपने गृहनगर लौटे और एक जंगल में मिलने की बात तय की। चूंकि चारों परस्पर एक-दूसरे को अपनी गूढ़ विद्याओं व सिद्धियों को बताना चाहते थे, अतः इसके लिए जंगल से उपयुक्त अन्य कोई स्थान नहीं हो सकता था। जब चारों जंगल में एक स्थान पर एकत्रित हुए तो वहां उन्हें शेर के शरीर की एक हड्डी पड़ी हुई मिली। एक ब्राह्मण ने कहा कि मैं अपनी विद्या से इस एक हड्डी से शेर का पूरा अस्थि पंजर बना सकता हूं।' उसने ऐसा कर भी दिखाया। तब दूसरे ब्राह्मण ने कहा कि मैं इसे त्वचा, मांस और रक्त प्रदान कर सकता हूं।' फिर उसने यह कर दिया। अब उन लोगों के समक्ष एक शेर पड़ा था, जो प्राणविहीन था। अब तीसरा ब्राह्मण बोला कि मैं इसमें अपनी सिद्धि के चमत्कार से प्राण डाल सकता हूं।' चौथे ब्राह्मण ने उसे यह कहते हुए रोका, 'यह मूर्खता होगी। हमें तुम पर विश्वास है, किंतु यह करके न दिखाओ।' किंतु तीसरे ब्राह्मण का तर्क था कि ऐसी सिद्धि का क्या लाभ जिसे क्रियान्वित न किया जाए। उसका हठ देखकर चौथा ब्राह्मण तत्काल पास के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। तीसरे ब्राह्मण के मंत्र पढ़ते ही शेर जीवित हो गया। प्राणों के संचार से शेर को आहार की आवश्यकता महसूस हुई और उसने सामने मौजूद तीनों ब्राह्मणों को मारकर खा लिया। चौथे ब्राह्मण ने समझदारी से अपने प्राण बचा लिए।

कथा का सार- किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणामों पर भली-भांति विचार कर लेना चाहिए, अन्यथा विपरीत स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।

7 अंतर खोजें

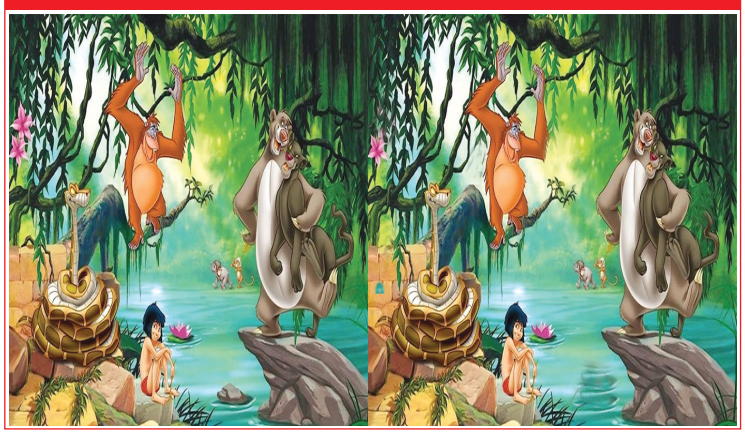

जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951

मेष लेनदारी वसूल करने के प्रयास सफल रहेंगे। व्यावसायिक यात्रा मनोनुकूल रहेगी। भाग्य का साथ रहेगा। कारोबार में वृद्धि होगी। समय पर कर्ज चुका पाएंगे।

वृषभ कार्यस्थल पर सुधार व परिवर्तन से भविष्य में लाभ होगा। शत्रु सक्रिय रहेंगे। पुराना रोग उभर सकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। शारीरिक कष्ट संभव है।

मिथुन कोर्ट व कचहरी के कार्य मनोनुकूल रहेंगे। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी में उन्नति होगी। निवेशादि करने का मन बनेगा।

कर्क व्यवसाय ठीक चलेगा। आय में निश्चितता रहेगी। धनागम होगा। प्रतिद्वंद्वी अपना रास्ता छोड़ देंगे। वाहन व मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें।

सिंह स्थायी संपत्ति की दलाली बड़ा लाभ दे सकती है। रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। सभी ओर से खुश खबरें प्राप्त होंगी।

कन्या नौकरी में उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे। ऐश्वर्य के साधनों पर व्यय होगा। आय के साधनों में वृद्धि होगी। भाग्योन्नति के प्रयास सफल रहेंगे।

तुला लाभ के अवसर हाथ आएंगे। व्यापार-व्यवसाय ठीक चलेगा। निवेश शुभ रहेगा। पार्टी व पिकनिक का आनंद मिलेगा। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी।

वृश्चिक प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। पुराना रोग उभर सकता है। दुःखद समाचार प्राप्त हो सकता है। विवाद से क्लेश संभव है।

धनु व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। प्रयास सफल रहेंगे। पराक्रम बढ़ेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे।

मकर शुभ समाचार प्राप्त होंगे। नौकरी में अधिकार मिल सकते हैं। शेयर मार्केट से लाभ होगा। बाहर जाने का मन बनेगा। बड़ा काम करने की योजना बनेगी। लाभ होगा।

कुम्भ निवेश शुभ रहेगा। अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। व्यापार-व्यवसाय मनोनुकूल लाभ देगा। सुख के साधनों पर व्यय होगा।

मीन व्यवसाय ठीक चलेगा। आय बनी रहेगी। वाणी पर नियंत्रण रखें। हल्की हंसी-मजाक न करें। किसी अपरिचित व्यक्ति पर भरोसा न करें। चिंता तथा तनाव रहेंगे।

बॉलीवुड | मन की बात

खाने पीने की तरह नार्मल हो फीमेल प्लेजर : काजोल

फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज एक्ट्रेस काजोल इन दिनों लस्ट स्टोरीज-2 को लेकर चर्चा में हैं। उनकी यह फिल्म लस्ट स्टोरीज का सीक्वल है, जो कि 2018 में रिलीज हुई थी। सेकेंड पार्ट में काजोल प्रमुख भूमिका में हैं। एक्ट्रेस की यह फिल्म 29 जून को रिलीज हो रही है। लस्ट स्टोरीज 2 को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म का कंटेंट काफी बोल्ड है। हाल ही में काजोल ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ चीजों में किस तरह बदलाव हुआ है, और पहले की तुलना में चीजें अब कितनी बदल गई हैं।एक पोर्टल को दिए इंटरव्यू में काजोल ने कहा कि फीमेल प्लेजर को नॉर्मलाइज कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह हमारी जिंदगी का नॉर्मल पार्ट है। उन्होंने कहा, एक वक्त पर हम इस बारे में खुलकर बात करते थे। बाद में हमने इस बारे में बात करना बंद कर दिया। लेकिन, आखिरकार यह हमारी जिंदगी का हिस्सा है, और हम इसके बिना नहीं रह सकते। मुझे लगता है कि इसे उस तरह नॉर्मलाइज किया जाना चाहिए, जिस तरह हमने ड्रिंकिंग और ईटिंग को नॉर्मलाइज किया है। यह बिल्कुल हमारी बातचीत का हिस्सा बनाने वाली बात है। इसके बारे में बिल्कुल बात न करना इस तरह के मुद्दे को और बढ़ावा देता है, और लोगों में इसे लेकर और अटेंशन बना रहता है। काजोल ने कहा, पहले फिल्मों में लस्ट का मतलब पहले होता था कि दो फूल आपस में मिल रहे। दो गुलाब के फूल आपसे में मिलाए जाते हैं, और बस हो गया। इसके बाद लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है। तो मुझे लगता है कि हम अब आगे बढ़ चुके हैं, और लस्ट स्टोरीज 2 जैसा कुछ बनाने के बारे में सोचा। मुझे लगता है कि सिनेमा सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती है। काजोल ने कहा, मुझे नहीं लगता कि अमर प्रेम कहानियों में आज के जमाने में कोई भी यकीन रखता है। कोई किसी के लिए मरना पसंद नहीं करेगा।

जुलाई में रिलीज होगी शाहरुख की फिल्म 'जवान' का टीजर

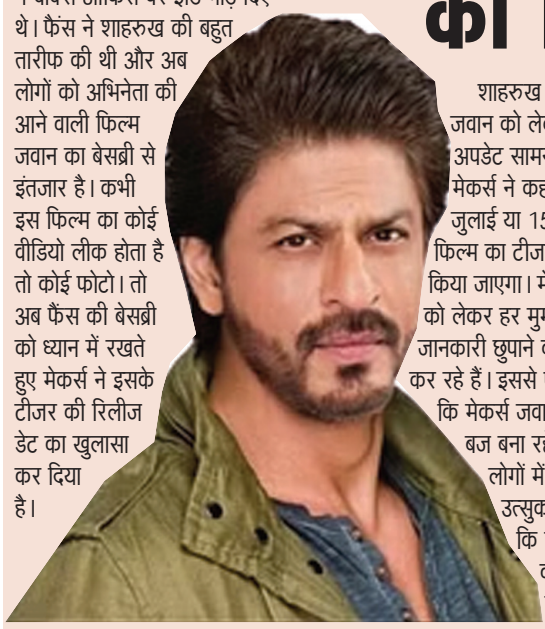

शाहरुख खान इन दिनों अपने टशन में हैं। बीते कुछ समय पहले उनकी फिल्म पठान सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए थे। फैंस ने शाहरुख की बहुत तारीफ की थी और अब लोगों को अभिनेता की आने वाली फिल्म जवान का बेसब्री से इंतजार है। कभी इस फिल्म का कोई वीडियो लीक होता है तो कोई फोटो। तो अब फैंस की बेसब्री को ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने इसके टीजर की रिलीज डेट का खुलासा कर दिया है।

शाहरुख खान की जवान को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मेकर्स ने कहा है कि 7 जुलाई या 15 जुलाई को फिल्म का टीजर रिलीज किया जाएगा। मेकर्स फिल्म को लेकर हर मुमकिन जानकारी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे फायदा यह है कि मेकर्स जवान को लेकर बज बना रहे हैं। ऐसे में लोगों में जानने की उत्सुकता बनी रहेगी कि फिल्म में ऐसा क्या होने वाला है जो मेकर्स

इतना छुपा रहे हैं। अब यह भी बताया जा रहा है कि फिल्म की रिलीज से ठीक दो महीने पहले इसका प्रोमोशन शुरू होने वाला है। शाहरुख और फिल्म के निर्देशक एटली इसे काफी बड़े स्तर पर लॉन्च करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि इतने भव्य स्तर पर दर्शकों ने अभी तक बॉलीवुड की किसी भी फिल्म के टीजर को लॉन्च होते नहीं देखा होगा। इसमें शाहरुख को पहले कभी न देखे गए अवतार में देखा जाएगा। उन्हें देख दर्शक हैरान रह जाएंगे।

संदीप के साथ मेगा बजट की फिल्म बनायेंगी कंगना

अपने तीखे और तंज भरे बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाली कंगना रणौत इन दिनों अपनी आगामी फिल्म इमरजेंसी को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म में अभिनेत्री अभिनय के साथ-साथ निर्देशन की कमान भी संभाल रही हैं। यहां तक की इमरजेंसी का निर्माण भी कंगना ने खुद ही किया है। जहां एक तरफ कंगना रणौत देश की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना पर बन रही फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी खबर आ रही है जो क्वीन के फैंस को खुश कर सकती हैं।

दरअसल, कंगना रणौत ने निर्माता संदीप सिंह के साथ एक बिग बजट फिल्म के लिए हाथ मिलाया है।

इमरजेंसी को लेकर देशभर में हो रही हलचल के बीच कंगना रणौत ने खुद संदीप सिंह के साथ अपने इस प्रोजेक्ट का एलान कर दिया है। हालांकि, अभी इस आगामी मेगा बजट फिल्म को लेकर और कोई डिटेल सामने नहीं आई है। दावा किया जा रहा है कि फिल्म के नाम और इसके निर्देशक की घोषणा जल्द ही की जाएगी। इतना ही नहीं यह भी बताया जा रहा है कि कंगना और संदीप की इस फिल्म की शूटिंग अगले साल की शुरुआत में शुरू की जाएगी।

अभिनेत्री कंगना रणौत ने फिल्म निर्माता संदीप सिंह के साथ अपने इस कोलैबोरेशन की घोषणा करते हुए कहा, संदीप और मैं 13 साल से ज्यादा समय से दोस्त हैं और लंबे समय से साथ में एक फिल्म करना चाहते थे। अब क्योंकि हमें सही विषय और

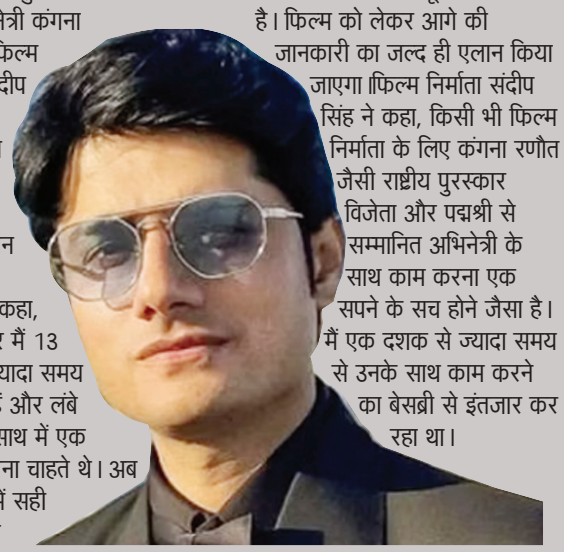

भूमिका मिल गई है तो यह जल्द ही रिलीज होने के लिए तैयार है। यह मेरे करियर की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म और शानदार भूमिका होने वाली है। फिल्म को लेकर आगे की जानकारी का जल्द ही एलान किया जाएगा।फिल्म निर्माता संदीप सिंह ने कहा, किसी भी फिल्म निर्माता के लिए कंगना रणौत जैसी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और पद्मश्री से सम्मानित अभिनेत्री के साथ काम करना एक सपने के सच होने जैसा है। मैं एक दशक से ज्यादा समय से उनके साथ काम करने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था।

अजब-गजब | लोगों का मानना पड़ता है अजीब नियम!

इस गांव के हर घर का दरवाजा है हरा

हर देश के अपने अलग-अलग नियम होते हैं जिनको वहां के लोग मानते हैं। पर कई बार उसी देश में कुछ ऐसे इलाके भी होते हैं जिनमें देश के नियम से अलग कानून का पालन किया जाता है। कोई नहीं जानता कि उन्हें कब से बनाया गया, पर लोग परंपरा की तरह उसे मानते चले आते हैं। ऐसा ही नियम ब्रिटेन के एक गांव में भी है। इस गांव को बेहद कड़े नियमों वाला माना जाता है जिसे भूलकर भी यहां के लोग नहीं बदलते।

डेली स्टार न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार वेंटवर्थ नाम के ब्रिटिश गांव को टस से मस ना होने वाला गांव माना जाता है। गांव में बेहद अजीबोगरीब नियम हैं। इसका पालन लोग इसलिए करते हैं जिससे वो यहां के आर्किटेक्चर को बचा सकें और परंपराओं को आगे तक के लिए जारी रख सकें। गांव में सिर्फ एक दुकान है, दो पब हैं और एक ही रेस्टोरेंट है। यहां लोग बिल्कुल भी हड़बड़ी में नहीं रहते हैं।

वेंटवर्थ गांव में घूमने के लिए कई लोग आते हैं, पर यहां बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। गांव में ग्रीन-डोर पॉलिसी का पालन किया जाता है। यानी हर दरवाजा हरे रंग का ही होता है। गांव का संचालन एक ट्रस्ट करता

है जो यहां कोई बदलाव नहीं करना चाहता। इसे वैसे ही रखना चाहता है जैसे ये हमेशा से था। गांव में 1400 लोग रहते हैं। 300 से अधिक वर्षों से, ट्रस्ट के पास क्षेत्र में निर्णय लेने की शक्ति है, जिसके कारण संपत्तियों में 95त्न स्वामित्व हो गया है, जबकि ग्रामीणों के पास वास्तव में अपने घर नहीं हैं, यानी वो उन घरों के मालिक नहीं हैं। इसके बजाय वे किरायेदार हैं और घरों के स्वामित्व का दावा करने में असमर्थ हैं, और जब किसी परिवार के सभी सदस्यों की मौत हो जाती है, यानी ब्लड लाइन खत्म हो जाती है तो किराया बढ़ जाता है। घर में किसी भी तरह का बदलाव करने के लिए लोगों को प्रशासन की अनुमति लेनी पड़ती है। एस्टेट के ग्राम प्रमुख अलेक्जेंडर ने उन संपत्तियों के बारे में बात की, जिन्हें देखकर समझ आ जाता था कि वो वेंटवर्थ का हिस्सा हैं, क्योंकि उनके दरवाजे हरे होते थे। उन्होंने कहा- जब आप वेंटवर्थ में ड्राइव करते हैं और देखते हैं कि सभी दरवाजे हरे हैं, तो आपको पता चलता है कि ये गांव एक एस्टेट गांव है। ये एक हेरिटेज का हिस्सा है। जब भी कोई यहां आता है, उसे तुरंत पता चल जाता है कि ये वेंटवर्थ ही है।

इस देश में कुत्तों को हो रहा डिप्रेशन! घुमाने ले जाने की दी सलाह

जब से कोरोना महामारी ने दुनिया में तबाही मचाई है, तब से ही लोग बीमारी के साथ-साथ डिप्रेशन का भी शिकार होते जा रहे हैं। घरों में बंद रहने के कारण, उन्हें अवसाद की समस्या हो रही है। ऐसे में डॉक्टर्स लोगों को घूमने-फिरने की भी सलाह देते हैं। पर हाल ही में ब्रिटेन के डॉक्टर ने, इंसानों की ही तरह, कुत्तों को भी घुमाने ले जाने की सलाह दी है, क्योंकि यहां उन्हें डिप्रेशन हो रहा है। जी हां, आपने सही पढ़ा, ब्रिटेन में कुत्ते भी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में एक चिकित्सक मालिकों को सलाह दे रहे हैं कि वो उन्हें भी छुट्टियों पर घुमाने ले जाएं। डेली स्टार न्यूज़ वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार लियॉन टावर्स एक डॉग बिहेवियरिस्ट हैं जो डॉग ओनर्स से आग्रह कर रहे हैं कि वो इस गर्मी में अपने कुत्तों को भी वैकेशन पर लेकर जाएं और अपने साथ एंजॉय करवाएं। उन्होंने कहा कि संवेदी संवर्धन उनकी खुशी की चाबी है और इसी से उनका समग्र कल्याण होता है। उन्होंने कहा- हमारे 100 में से 99 कुत्तों को पर्याप्त मानसिक उत्तेजना नहीं मिल रही है। अगर आपका कुत्ता पूरे दिन सिर्फ सो रहा है, तो मुमकिन है कि वो डिप्रेस्ड है। इस लिए मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि कुत्तों को बी वैकेशन पर ले जाया जाए। रोज़मर्रा की दिनचर्या से मुक्त करना और कुत्तों को नए दृश्यों और गंधों के साथ उत्तेजक वातावरण में ले जाना उसे आवश्यक संवेदी संवर्धन प्रदान करता है। लियॉन टावर्स के अनुसार, कुत्तों के लिए वैकेशन की सबसे अच्छी एक्टिविटी तैराकी है। समुद्र तट कुत्तों के लिए भी बहुत अच्छा है, उन्हें रेत पर और खारे पानी में चलने से फायदा होगा, क्योंकि वे अपने पंजे पर पैड के माध्यम से पोषक तत्वों को एब्सॉर्ब करते हैं। लियॉन ने कहा कि तैराकी कुत्तों को आवश्यक स्वास्थ्यवर्धक खुराक प्रदान करती है। ये न केवल उनके पूरे मस्तिष्क को व्यस्त रखती है, बल्कि डॉग-फ्रेंडली बीच कुत्तों को बेहद खास अनुभव भी प्रदान करते हैं। उन्होंने बताया कि कुत्ते बीच पर घूमने से 50 फीसदी तक ज्यादा एक्टिव रहते हैं।

फोनपे पर गरमाई मप्र की सियासत

» कांग्रेस ने पूछा-एप से मध्य प्रदेश में रिश्वत नहीं ली जाती

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

भोपाल। प्रदेश में पोस्टर वॉर में फोन पे की एंट्री हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पोस्टर में फोनपे के क्यूआर कोड और लोगो के इस्तेमाल पर फोन पे ने कांग्रेस को चेतावनी दी थी। इस पर अब कांग्रेस ने पलटवार कर फोन पे से सवाल किया है। कांग्रेस ने पूछा कि आपके एप से मध्य प्रदेश में रिश्वत नहीं ली जाती? मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर फोन पे से सवाल करते हुए ट्वीट किए हैं। इसमें लिखा है, 'प्रिय फोन पे टीम, आप किस पोस्टर या बैनर की बात कर रहे हैं, कृपया उल्लेखित, स्पष्ट करें, सार्वजनिक करें।

क्या फोन पे अपने अधीन ट्रांसफर होने वाले पैसों के उपयोग के लिए भी उत्तरदायी है? क्या आप फोन पे के उपयोग-दुरूपयोग के मामले को भविष्य में मॉनिटर करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि आपके एप के माध्यम से ट्रांसफर किया गया पैसा कभी भी रिश्वत या भ्रष्टाचार के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा? क्या आप प्रमाणित करेंगे कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं है? और यदि है तो उसकी दर क्या है? क्या आपके किसी पदाधिकारी ने भाजपा के किसी नेता, सरकार से पिछले 7 दिनों में कोई संवाद नहीं किया है? कृपया स्पष्टता और पारदर्शिता के साथ आएं अन्यथा आपके इस ट्वीट को राजनीति से प्रेरित और एक दल विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य में गिना जाएगा और आपके विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

कंपनी ने लोगो के इस्तेमाल पर की थी आपत्ति

इससे पहले फोन पे ने उसके लोगो के इस्तेमाल को लेकर ट्वीट किया था। इसमें फोन पे ने लिखा था कि कोई तीसरा पक्ष उसके ब्रांड लोगो का इस्तेमाल नहीं कर सकता। चाहे व राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लगाए पोस्टर में फोन पे के स्कैनर के साथ मुख्यमंत्री का फोटो लगाया था। इस पर फोन पे ने आपत्ति जताते हुए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच पोस्टर वॉर चल रहा है। पहले कमलनाथ के करप्शननाथ लिखकर वांटेड के पोस्टर लगाए गए। इसके जवाब में कांग्रेस ने शिवराज के घोटाला राज के पोस्टर लगाए। इसके बाद शिवराज का एक और पोस्टर सामने आया। जिसमें लिखा है कि 50 फीसदी लाओ, फोन पे काम कराओ।

क्यों न पढ़ाएं उत्कृष्ट देशभक्त की जीवनी: शिवराज

मध्यप्रदेश में वीर सावरकर शिक्षा के सिलेबर्स में क्यों नहीं पढ़ाने चाहिए। वीर सावरकर काले पानी में रहे और 2-2 जन्मों की सजा हुई। देश के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दिया। सेल्यूलर जेल में जब जाकर देखते हैं, किस तरह के सेल में सावरकर रहते थे। उनके दूसरे भाई भी उसी जेल में बंद रहे थे, ऐसे लोगों की जीवनी क्यों नहीं पढ़ाई जाए। बिल्कुल पढ़ाई जाएगी, जो उत्कृष्ट देशभक्त रहे हैं। गौरतलब हो कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने स्कूली पाठ्यक्रम में वीर सावरकर को शामिल करने का फैसला किया है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इस फैसले के पक्ष में कहा कि वीर सावरकर महान क्रांतिकारी थे।

सिलेबस में सावरकार, क्रांतिकारियों का अपमान : कांग्रेस

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि वीर सावरकर को किस हैसियत से शामिल करना चाहते हैं? यह बड़ा सवाल है और अफसोसजनक भी है। सावरकर के माफी मांगने के कई पत्र हमने पढ़े हैं, जो सोशल मीडिया पर आ चुके है। ऐसे व्यक्ति को क्रांतिकारी बताकर सिलेबस में जोड़ना शर्मनाक है और यह तो फीडम फाइटर की तौहीन है। हम देश को चाहने वाले लोग हैं। वह भाजपा के मार्गदर्शक है, यह बात ही शर्मनाक है। हम तो इसका विरोध करेंगे। देश के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारियों का इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए न कि माफी मांगने वाले का।

वीना कुमारी मीना को प्रमुख सचिव आबकारी व गन्ना की जिम्मेदारी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। शासन ने प्रदेश में पांच आईएएस और चार पीपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। गोरखपुर में एएसपी सुरक्षा रविंद्र कुमार वर्मा प्रथम को अभिसूचना मुख्यालय भेजा गया है। वहीं, अभिसूचना में तैनात घनश्याम को गोरखपुर में एएसपी सुरक्षा बनाया गया है।

सात आईएएस के तबादले

गोरखपुर में एएसपी यातायात डॉ. महेंद्र पाल सिंह को साइबर क्राइम मुख्यालय भेजा गया है। उनके स्थान पर गोरखपुर में तैनात श्यामदेव को एएसपी यातायात बनाया गया है। बीना कुमारी मीना आईएएस जो प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग तथा उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग एवं महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में थी अब प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग तथा आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पद पर मूलरूप से तैनात करते हुए प्रमुख सचिव, महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन का अतिरिक्त प्रभार यथावत बनाये रखा गया है। आलोक कुमार प्रमुख सचिव, नियोजन, कार्यक्रम क्रियान्वयन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उ.प्र. शासन एवं नोडल अधिकारी, वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी लखनऊ को वर्तमान पद के साथ प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद तथा उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग, उत्तर प्रदेश शासन का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया गया है।

प्रभु नारायण सिंह सचिव, राजस्व विभाग, उ.प्र शासन एवं राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश तथा आयुक्त, चकबंदी, उत्तर प्रदेश को आयुक्त, गन्ना की जिम्मेदारी दी गई हैं। नवीन कुमार जी.एस विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग,थे वह अब विशेष सचिव, राजस्व विभाग, उ.प्र. शासन एवं प्रभारी राहत आयुक्त होंगे। बाल कृष्ण त्रिपाठी विशेष सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन होंगे। जबकि शुक्रवार को बृजेश कुमार एसीओ ग्रेटर नोएडा बनाए गये तथा योगेंद्र यादव को कमिश्नर निशक्तजन और अपर सचिव समाज कल्याण में तैनाती दी गई है।

सुकमा में शिक्षक की डंडे से पीट-पीटकर हत्या

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में अभी भी नक्सलियों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने बुरकापाल गांव के 10 लोगों का बंदूक की नोंक पर अपहरण कर अपने साथ उन्हें जंगल में ले गए।

नक्सली इन इलाकों में अपनी जनताना सरकार चलाते है, जहां जनअदालत कर फैसला किया जाता है। गुरुवार 28 जून को नक्सलियों ने ताड़मेटला गांव में जनआदलत लगाई। वहां उन 10 लोगों को सैकडो ग्रामीणों के सामने पेश किया गया। नक्सली अब आम ग्रामीणों को अगवा कर उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। इतना ही नहीं पुलिस के मुखबिर होने के शक में उनकी हत्या भी की जा रही है। बीते दिनों सुकमा में नक्सलियों ने 10 ग्रामीणों का अपहरण किया जिन्हें जनअदालत लगाकर पहले प्रताड़ित किया गया, उसके बाद एक उपसरपंच और एक शिक्षक की हत्या कर दी। वहीं 8 लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया है।

फोटो :4 पीएम

विरोध स्थानान्तरण नीति का पालन ना किए जाने और मनमाने ढंग से ट्रांसफर किए जाने के विरोध में लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों ने लोक निर्माण कार्यालय के सामने जमकर किया प्रदर्शन। कर्मचरियों ने आरोप लगाया कि जिन कर्मचारियों ने इसका विरोध किया, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने उन कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। कर्मचारियों ने माँग की है कि निलंबित कर्मचारियों को तुरंत बहाल किया जाये, सभी का ट्रांसफर इस स्थानांतरण नीति के अनुरूप किया जाए।

नोवाक को धकेल कर अल्कारेज टॉप पर

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

पेरिस। विंबलडन 2023 के लिए फ्रेंच ओपन में इस बार जीत हासिल कर ऐतिहासिक रुप से 23 ग्रैंडस्लैन जीतने की उपलब्धि हासिल करने वाले सर्बियाई खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के फैंस के लिए बुरी खबर है। इस बार विंबलडन में चार बार के गत चैम्पियन नोवाक जोकोविच को वरीयता नहीं मिली है बल्कि उनकी जगह स्पेन के 20 वर्षीय कार्लोस अल्काराज को शीर्ष पर काबिज किया गया है।

करियर में कुल 23 ग्रैंडस्लैम जीतकर इतिहास रचने वाले नोवाक जोकोविच ने पेरिस में आयोजित हुए फ्रेंच ओपन 2023 में जीतने के बाद से कोई टूर्नामेंट नहीं खेला है। वहीं अल्कारेज ने फ्रेंच ओपन 2023 खेलने के बाद भी कुछ टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है। आल इंग्लैंड क्लब ने एटीपी और डब्ल्यूटीए रैंकिंग के मुताबिक इस बार पुरुष वर्ग में कार्लोस अल्काराज और महिला वर्ग में चार बार की ग्रैंड स्लैम विजेता पोलैंड की 22 वर्षीय इगा स्वियातेक को शीर्ष स्थान दिया है। जानकारी के मुकाबिक सोमवार को पुरुष रैंकिंग में नोवाक जोकोविच को मात देकर अल्कराज ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। बता दें कि इससे पहले इसी महीने 11 जून को फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट में नोवाक जोकोविच ने 23वां ग्रैंडस्लैम खिताब जीता था। हालांकि इस टूर्नामेंट के बाद उन्होंने कोई और मुकाबला नहीं खेला है। इस कारण अब नोवाक जोकोविच दूसरे पायदान पर खिसक गए है। अल्काराज ने क्वींस क्लब में ग्रासकोर्ट की तैयारी वाले टूर्नामेंट में खिताब जीता था।

इस टूर्नामेंट को जीतने के बाद ही उनके अंकों में उछाल आया और वो रैंकिंग में शीर्ष पायदान पर पहुंच गए। बता दें कि नोवाक जोकोविच के लिए पिछला कुछ समय काफी अच्छा रहा है। इस दौरान उन्होंने बीते चार विम्बलडन खिताब (कुल सात विम्बलडन ट्राफियां) पर कब्जा जमाया है।

विम्बलडन में वरीयता नहीं मिली

अगले हफ्ते से विंबलडन का आगाज

बता दें कि विंबलडन 2023 की शुरुआत सोमवार से हो रही है और 32 पुरुष वरीय खिलाड़ियों में कैस्पर रूड चौथी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। उनके बाद स्टेफानोस सिटसिपास, होल्गर रूने, यानिक सिनर, टेलर फिट्ज और फ्रांसेस टियाफो शामिल हैं। एक साल पहले उप विजेता रहे निक किर्गियोस को 31वीं वरीयता मिली है। दो बार के विंबलडन चैम्पियन एंडी मरे की रैंकिंग 39 है जिससे उन्हें वरीयता नहीं मिली है। स्वियातेक अप्रैल 2022 के बाद से शीर्ष रैंकिंग पर काबिज हैं और चार ग्रैंडस्लैम खिताब जीत चुकी हैं जिसमें से हाल में उन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था। वह हालांकि विंबलडन में चौथे दौर से आगे नहीं पहुंच सकी हैं।

सुबह-सुबह की बारिश से नहाई राजधानी

» मौसम विभाग का अलर्ट और तेज होगी वर्षा

» जगह-जगह जलभराव, लोग रहे परेशान

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जून के आखिरी दिन सुबह-सुबह जमकर बारिश हुई। इससे पारे में गिरावट हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अभी चार-पांच दिनों तक ऐसे ही बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी है पूरे प्रदेश में मूसलाधर बारिश होगी। वहीं दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में बारिश और कही-कहीं बूंदाबांदी चल रही है। दिल्ली-एनसीआर में कल सवेरे से ही रुक-रुक कर बारिश हो रही है।

मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि शुक्रवार को बारिश होगी। उधर पांच जुलाई तक दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश का अंदेशा नहीं है। इतना जरूर है कि बीच-बीच में फुहारें पड़ती रहेंगी। इससे उमस भरे मौसम से दिल्ली-एनसीआर के लोगों को दो-चार होना पड़ सकता है। राजधानी में सुबह की बारिश से कई इलाकों में जलभराव हुआ। इस कारण अपने गंतव्य पर जाने वाले लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। बारिश के दौरान आलमबाग, गोमतीनगर, इंदरानगर, अलीगंज, जानकीपुरम, चारबाग व पुराने लखनऊ के कई इलाकों में जलभराव हो गया। बारिश बंद होने के बाद गलियों व सड़कों से पानी निकलने के बाद लोग घरों से निकल सके। कई जगह नाले चोक व गए और घरों में पानी भर गया।

अधिकारियों की लापरवाही से राजधानी के राजेंद्र नगर इलाके में सड़क धंस गयी जिसकी वजह से वहां पर एक ट्रक पलट गयी।

अखिलेश ने वीडियो ट्वीट कर सरकार को घेरा

वाराणसी। वाराणसी में हुई बारिश से शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया। झमाझम बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी। अंधरापुल में हुए जलभराव का एक वीडियो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडिल से ट्वीट करते हुए भाजपा पर तंज कसा है।

राज्यपाल के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएंगे : स्टालिन

केंद्र पर भड़की डीएमके- अपने आरोपी मंत्रियों पर करे कार्रवाई

» राज्यपाल के मंत्री सेंथिल बालाजी को हटाने के फैसले पर हुआ विवाद

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चेन्नई। तमिलनाडु में राज्यपाल आरएन रवि द्वारा राज्य सरकार के मंत्री सेंथिल बालाजी को पद से हटाने और बाद में अपने फैसले को वापस लेने से सियासी पारा चढ़ गया है। डीएमके राज्यपाल पर हमलावर है और केंद्र सरकार पर भी निशाना साध रही है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने जहां राज्यपाल के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही है, वहीं उनकी पार्टी ने जगह-जगह पोस्टर लगा दिए हैं।

इन पोस्टरों में उन केंद्रीय मंत्रियों की तस्वीरें लगाई गई हैं, जिनके खिलाफ कई मामले चल रहे हैं और वह अभी भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हैं। बता दें कि तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने एक दुर्लभ फैसले के तहत तमिलनाडु सरकार के मंत्री सेंथिल बालाजी को मंत्रि परिषद से बर्खास्त कर दिया था। एक विज्ञप्ति जारी कर राज्यपाल ने कहा कि बालाजी कई गंभीर मामलों में कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। ऐसे में मंत्री रहते हुए, वह जांच को प्रभावित कर सकते हैं। विज्ञप्ति में कहा गया कि ऐसी आशंका है कि सेंथिल बालाजी के मंत्रिपरिषद में बने रहने से निष्पक्ष जांच सहित कानूनी प्रक्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। हालांकि बाद में राज्यपाल ने अपने इस फैसले को वापस ले लिया और कहा कि वह अटॉर्नी जनरल से सलाह के बाद इस मामले पर कोई फैसला करेंगे।

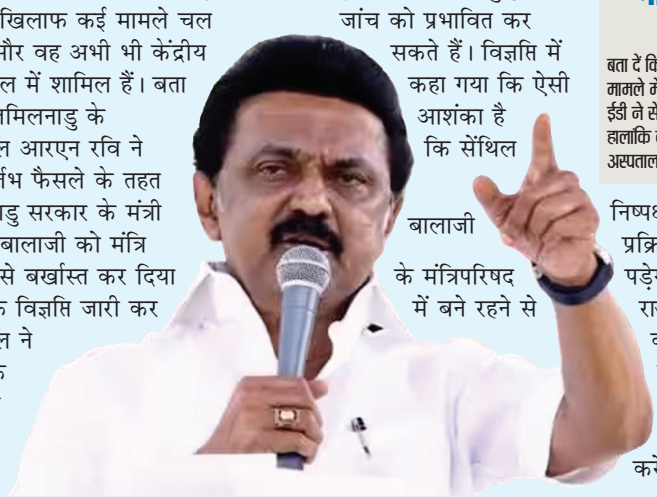

नौकरी के बदले नकदी मामले में गिरफ्तार हैं सेंथिल बालाजी

बता दें कि सेंथिल बालाजी नौकरी के बदले नकदी मामले में जांच का सामना कर रहे हैं। बीते दिनों ईडी ने सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार किया था। हालांकि बालाजी की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में शिफ्ट किया गया।

2047 तक बनाएंगे भारत को विकसित राष्ट्र : मोदी

» छात्रों का आरोप : अतिरिक्त उपस्थिति के लिए दिया प्रलोभन

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

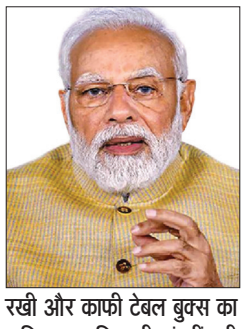

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय शताब्दी वर्ष का समापन समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम भारत को 2047 तक एक विकसित भारत का निर्माण करना चाहते हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने डीयू की तीन इमारतों की आधारशिला रखी और काफी टेबल बुक्स का एक सेट भी जारी किया। पीएम ने कहा कि भारत विश्व की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। विकसित भारत का निर्माण करना हमारा लक्ष्य है। विश्व के लोग भारत को जानना चाहते हैं। विश्व में भारतीय युवाओं के लिए मौके बन रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा हेरिटेज म्यूजियम बनने जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय यूनिवर्सिटी की ग्लोबल पहचान बढ़ रही है, विश्व में भारत का गौरव बढा है। देश का युवा कुछ नया करना चाहता है। देश में स्टार्टअप की संख्या अब लाख के पार है। बड़ी कंपनियों ने भारत में निवेश का फैसला लिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में छात्रों की भीड़ जुटाने के लिए उन्हें प्रलोभन दिया गया। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने छात्रों से काले कपड़े न पहनकर आने के लिए कहा गया था।

पसमांदा मुस्लिमों को मिले आरक्षण : मायावती

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। पीएम नरेंद्र मोदी बीते दिनों भोपाल के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड और पसमांदा मुसलमानों को लेकर दिए बयान पर भाजपा को घेरा है। बीएसपी प्रमुख मायावत ने प्रतिक्रिया दी है। बीएसपी चीफ ने ट्वीट कर लिखा, पीएम नरेन्द्र मोदी द्वारा भोपाल में बीजेपी के कार्यक्रम में सार्वजनिक तौर पर यह कहना कि भारत में रहने वाले 80 प्रतिशत मुसलमान 'पसमांदा, पिछड़े, शोषित' हैं, यह उस कड़वी जमीनी हकीकत को स्वीकार करना है जिससे उन मुस्लिमों के जीवन सुधार हेतु आरक्षण की जरूरत को समर्थन मिलता है।

मायावती ने कहा, अब ऐसे हालात में बीजेपी को पिछड़े मुस्लिमों को आरक्षण मिलने का विरोध भी बंद कर देने के साथ ही इनकी सभी सरकारों को भी अपने यहां आरक्षण को ईमानदारी से लागू करके तथा बैकलॉग की भर्ती को पूरी करके यह साबित करना चाहिए कि वे इन मामलों में अन्य से अलग हैं।

सियाज और सफारी में भिड़ंत, महिला सहित चार की मौत

डिवाइडर तोड़कर रॉन्ग साइड पहुंची कार

» लखनऊ - आगरा एक्सप्रेसवे पर हुआ दर्दनाक हादसा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में चार लोगों की मौत हो गई जबकि छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना मटसेना थाना क्षेत्र अंतर्गत लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे की है।

यहां सियाज कार और सफारी में भिड़ंत हो गई। हादसे में सियाज कार सवार तीन पुरुष और एक महिला की मौत हो गई। वहीं छह अन्य लोग घायल हो गए। सूचना पर एसएसपी आशीष तिवारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायलों को अस्पताल भेजा। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। बताया गया कि सियाज कार दिल्ली की तरफ से आ रही थी। अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़कर रॉन्ग साइड पर पहुंच गई। इसी समय लखनऊ की तरफ से आ रही सफारी कार से सामने से भिड़ गई। सियाज कार सवार चारों लोगों की मौत हो गई। जबकि सफारी सवार छह लोग घायल हो गए।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक बबिता चतुर्वेदी के लिए 4पीएम आस्था प्रिंटर्स, 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (यूपी) से मुद्रित एवं प्रकाशित। प्रधान संपादक- अर्चना दयाल, संपादक - संजय शर्मा, विधि सलाहकार: सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, मोहम्मद हैदर, वित्तीय सलाहकार: संदीप बंसल, कार्टूनिस्ट: हसन जैदी, दूरभाष: 0522- 4078371 | Email: daily4pm@gmail.com | website: www.4pm.co.in | RNI-UPHIN/2015/62233 डाक पंजी. सं- SSP/LW/NP-495/2018-2020
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।